fication schemes sponsored by the State Electricity Boards.

About 3,300 villages were electrified in the country during the period from 1st April, 1974 to 30th September, 1974. These include 147 villages electrified in Himachal Pradesh.

(b) The target is to electrify 11,818 villages in the country during 1974-75. These include 600 villages to be electrified in Himachal Pradesh

स्वर्गीय भी बी० के० कृष्ण मेनन द्वारा चल तथा प्रचल सम्पत्ति की राष्ट्र के नाम क्लीबत ।

5029 श्री लालजी भाई: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की क्रुया करेंगे जि

- (क) क्या स्वर्गीय श्री बो० के० ग्रष्ण मेनन ने वसीयत की है कि उपका मृत्यु के पश्चात् उनकी समस्त चल ग्रांग्य्यतन मध्यत्ति राष्ट्रको सोप दी जाये।
- (ख) यदिहा,तो उनकी चल ग्रीरश्रवल सम्पत्ति भा भ्रीरा क्या है , ग्रीर
- (ग) का उनहाने प्राना स्वीता में प्रधान मन्दर्भ अनुराव किया है । उन्हें प्रानी इच्छ नुशा अकी सम्पत्ति । उन्होंग सर सकती है।

प्रधान मंत्री, परमाणु कर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (्र) से (ग) क्षी बी • ते • एण मेनन कर्ष वनीयत जिसपर उरहान 1-10-1974 क हस्ताक्षर किए थे ग्रीप जिसे दो गवाहोंने नाक्ष्याकित किया था, 2 नवम्बर 1974 का उन्हीं नई दिल्ली निवाम स्थान पर एउ फाफ में पड़ी मिली था यह उस बक्षायत से अन्न है जो अप्रैल, 1974 में निष्पादित की रई वी भीर जो 'तरवाद' तथा 'ताविम' चल 'या ग्रचल सम्मलियों के अबंध में ही बी । इं बक्षीयत में इस प्रकार लिखा गया है।

'इस वस,यत के द्वारा मैं भारत, इस्लंड तथा श्रन्य जगहों पर स्थित अपना सप्पूर्ण सम्पत्ति चल तथा मचल, सुद सहित (तरवाद तथा तावशि सम्पत्तियो जिनकी वस।यत,पहले हो को जा चुका है) राष्ट्र के नाम इनके द्वारा वस।यत न रता है।

यह मेर। इच्छा है कि राष्ट्र क श्रार से प्रधान मता जा इसमें को गई वसायन कबूल करे श्रीर श्रपने पूर्ण विवक से जिस रूप में श्रयवा जिस उद्देश्य के 1 नए वे उचित समझे, ग्राम में लाये।

चल तथा प्रचल सम्पत्ति के नौरों की जानकारी ग्रभानहीं मला है, भूसरे वसायत तमें के द्वारा नामा द्रप्ट व्यक्तियां की, उपराितिखित तरवा है। या तविश मप्पात्त की वसीयत का गई है।

Regional Offices under Commissioner for S C and S T

5030 SHRI SAKTI KUMAR SARKAR:

> SHRI P. M. SAYEED: SHRI S. M. SIDDAYYA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be the tell to state

- (a) whether the Ministry of Law has opined that Commissioner for Scheduled Cartes and Scheduled Tribes should collect all data required by him through officers appointed directly under him and answerable to him alone, in order to ensure that he is able to collect information according to uniform norms laid down by him, and
- (b) if so, what action has been taken to let the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, appointed under a constitutional provision, collect information required by him through an idependent field organisation directly under